

रजिस्टर्ड नं० ०१०/६८० एम० १४.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 24 अक्टूबर, 1987/2 कार्तिक, 1909

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग नियुक्ति-I

अधिसूचनाएँ

शिमला-25 अगस्त, 1987

सं० पर० (नि-I) ए (3)-3/84--भाग-II--भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श से, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएँ नियम, 1973 जो कि अधिसूचना सं० 7-5/73-डी०१०(नियुक्ति), दिनांक 15-3-1973 द्वारा बनाये गये थे और समय-समय पर संशोधित किये गये हैं, में निम्नलिखित संशोधन सहर्ष करते हैं:—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules shall be called the Himachal Pradesh Administrative Services (Second Amendment) Rules, 1987.

(2) These rules shall come into force with effect from 1-2-1987.

2. *Amendment of Appendix II [Under rule 23 (b) (5)].*—For the existing entries at Sl. No. 21 & 31 of Appendix-II under rule 23 (b) (5) of the Himachal Pradesh Administrative Services Rules, 1973, the following shall be substituted:—

“21. Settlement Officer (Consolidation of Holdings) 250-00
31. Assistant Settlement Officer 250-00

आदेश द्वारा,
पी० के० मट्टू,
मुख्य मंचिव।

शिमला - 2, 19 सितम्बर, 1987

सं० पर(नि०-II)ए(3)-1/77-III.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग को अधिसूचना संख्या 2-6/71-नियुक्ति-II दिनांक 20-9-73 द्वारा प्रकाशित हिमाचल प्रदेश प्रतिलिपि सर्विस कमीशन (एर्जेंस्पशन प्रोम कन्सलटेशन) रेगुलेशन, 1973 द्वारा प्रकाशित, हिमाचल प्रदेश सरकार के आसाधारण राजपत्र दिनांक 21-9-73 में प्रकाशित किए गए थे, में सहर्व निम्नलिखित संशोधन करने का आदेश देते हैं :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These Regulations may be called the H.P. Public Service Commission (Exemption from Consultation) (11th Amendment) Regulations, 1987.
(2) These shall come into force at once.

2. **Amendment of the Schedule.**—In the schedule to the Himachal Pradesh Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1973, the following sub-items (x) and (xi) shall be added below in No. 8:—

(x) all posts under the Himachal Pradesh Administrative Tribunal;
(xi) 37-1/2% posts of Ayurvedic Chikitsa Adhikaries (Gazetted Class-II) recruitment to which is made on batch-wise basis.

आदेश द्वारा,
भगत चन्द्र नेगी,
मुख्य सचिव।

Shimla-2, the 19th September, 1987

No. 1-3/75-DP-(Apptt.I).—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to detail the following HPAS Officers on temporary duty to Kullu during ensuing Dussera festival, with effect from 30-9-1987 to 10-10-1987:—

1. Shri Subhas Chander, A.C. to D.C. Kangra at Dharamshala.
2. Shri Dhruv Vashist, Project Officer, DRDA, Una.
3. Shri Chherring Ram, S.D.O. (C) Udaipur, Himachal Pradesh.

2. The Governor is further pleased to order that the above officers shall be entitled to draw T.A. and D.A. as admissible under the Government of India's decision No. 18 below SR-36.

3. The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 is also pleased to appoint the aforesaid officers to be Executive Magistrate, with all the powers of an Executive Magistrate under the said code, to be exercised within the local limits of Kullu Sub-Division with effect from 30-9-1987 to 10-10-1987, subject to the conditions contained in the Himachal Pradesh Government Home Department letter No. Home-B-(B)(12)-5/84, dated 4-12-1984 and 28-12-1984.

By order,
P. S. RANA,
Secretary.

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Shimla-2, the 22nd August, 1987

No. Home (A)-A (9)-37/80-Part-IV.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Security Act, 1980 (Act No. 65 of 1980) the Governor, Himachal Pradesh is pleased to specify by general order that any person detained under section 3 of the said Act by Government or by the District Magistrates, authorised in this behalf, shall be detained in a police lock-up or kept in any jail in Himachal Pradesh subject to the conditions as to maintenance/discipline and punishment for breaches of discipline specified in the Himachal Pradesh Detenus (Conditions of Detention) Order, 1980.

Shimla-2, the 22nd August, 1987

No. Home (A)-A (9)-37/80-Part-IV.—In exercise of the powers vested in him under para-II of sub-section (3) of section 3 of the National Security Act, 1980 (Act No. 65 of 1980), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to authorise District Magistrates in Himachal Pradesh, within their respective jurisdiction, to exercise the powers of the State Government under sub-section (2) of section 3 of the aforesaid Act delegated *vide* this Government notifications of even number, dated the 27th May, 1985, 2nd September, 1986 and further extended *vide* notifications of even number, dated the 7th October 1985, 30th November 1985, 25th/27th February, 20th May, 2nd September, 24th November, 1986, 12th February, 1987 and 19-5-1987 for a further period of three months *w.e.f.* 25-8-1987 to 25-11-1987.

By order,
Kr. SHAMSHER SINGH,
Commissioner-cum-Secretary.

शिमला-171002, 24 अगस्त, 1987

संघ्या गृह (ए)-एफ(13)-1/87.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन नामतः गांव चौड़ी, जुन्या (तहसील व जिला शिमला) में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल के लिये बाधा मार्ग के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है। अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिये भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिये भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला ऐक्ट) अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और शमिकों को इलाके की किसी भूमि में प्रवेश करने और संवेदन करने और इस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति, जिसे उक्त परिक्षेत्र में भूमि के अर्जन पर कोई शापति हो तो वह इस अधिसूचना

के प्रकाशित होने के तीस दिनों के अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, शिमला (ग्रामीण) के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विनिर्दिष्ट

जिला: शिमला

तहसील: शिमला

ग्राम	खसरा नं 0	रकबा	
		विधा	विस्वा
1	2	3	4
चौड़ी	822/777 52	6 5	9 1
	योग . .	11	10

शिमला-71002, 25 अगस्त, 1987

सं 0 गृह (ए)-एफ (13)-5/86.—यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सावंजनिक प्रयोजन नामतः गांव ओगली, तहसील नाहन, जिला सिरमोर में पुलिस आवासीय भवन निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों और उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भूमि में प्रवेश करने और सरकार करने और उक्त धारा द्वारा अपेक्षित या अनुमत अन्य सभी कार्य करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

कोई भी ऐसा हितवद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होन की 30 दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, नाहन उप-मण्डल (उप-मण्डलीय अधिकारी नाहन, जिला सिरमोर, हिमाचल प्रदेश के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला: सिरमोर

तहसील: नाहन

गांव	खसरा नं 0	क्षत्र	
		बीधा	विस्वा
1	2	3	4
ओगली	205/158	00	05

आदेश द्वारा
एस० एस० कंवर,
आयुक्त एवं सचिव।

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 15th September, 1987

No. Udyog (Ka)3-2/86(R&P).—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Store Inspection Officer (Pharmacy), Class-II Gazetted, in the Department of Industries, Himachal Pradesh, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Industries Department Store Inspection Officer (Pharmacy) (Class-II Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1987.

(2) These Rules shall come into force from the date of issue of this Notification.

2. Rules.—The number of posts, classification, pay scale, qualification and method of Recruitment for the post of Store Inspection Officer (Pharmacy) in the Department of Industries shall be as specified in Annexure-A to this Notification.

ANNEXURE A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF STORE INSPECTION OFFICER (PHARMACY) (CLASS-II GAZETTED)

1. *Name of the post.*—Store Inspection Officer (Pharmacy).
2. *Number of posts.*—One.
3. *Classification.*—Class-II (Gazetted).
4. *Scale of pay.*—Rs. 825-25-850-30-1000/40-1200/50-1400-60-1580.
5. *Whether selection post or non-selection post.*—N.A.
6. *Age for direct recruits.*—“35 years and below.”;

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on *ad-hoc* or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on *ad-hoc* basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such *ad-hoc* or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/other categories of persons to the extent permissible under the general or special order of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the public sector corporation and autonomous bodies who happened to be Government servant before absorption in public sector corporation/autonomous bodies at the time of initial constitution of such corporation/autonomous bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector corporation/autonomous bodies who were/are subsequently appointed by such corporation/autonomous bodies and are/were finally absorbed in the service of such corporation/autonomous bodies after initial constitution of the public sector corporation/autonomous bodies.

Note 1.—The crucial date for determining the age limit should be the first day of the year in which the post(s) are advertised for inviting applications or notified to employment exchanges as the case may be.

Note 2.—Age and qualifications in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission, in case of the candidate is otherwise well qualified.

7. *Minimum educational and other qualifications required for direct recruits.*—**ESSENTIAL:** Should possess B. Pharma degree in pharmacy or Pharmaceutical Chemistry from a recognised University.

DESIRABLE QUALIFICATIONS:

Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. *Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.*—**AGE:** N.A.

EDUCATIONAL QUALIFICATION: N.A.

9. *Period of probation, if any.*—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. *Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, deputation transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.*—100% by deputation, failing which by direct recruitment.

11. *In case of recruitment by promotion, deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made.*—“By deputation from amongst Drug Inspectors of Health and Family Welfare Department, Himachal Pradesh working in pay scale of Rs. 750-1300 possessing essential qualifications as given under Col. 7.”.

Note 1.—In all cases of promotion *ad-hoc* service rendered in the feeder post upto 31-12-1983.

if any prior to the regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition:—

- (a) that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including *ad-hoc* service rendered upto 31-12-1983) in the feeder post, in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of considerations.

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person become in eligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

- (b) similarly, in all cases of confirmation, *ad-hoc* service rendered in the post upto 31-12-1983 if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service:

Provided that the *inter-se-seniority* as a result of confirmation after taking into account *ad-hoc* service shall remain unchanged.

- (c) *ad-hoc* service rendered after 31-12-1983 shall not be taken into account for confirmation/promotion purposes.

Note 2.—Provisions of Rules 10 and 11 are to be revised by the Government in consultation with the Commission as and when the number of posts under Rule 2 are increased.

12. *If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.*—Not applicable.
13. *Circumstances under which the H.P. Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.*—As required under the Law.

14. *Essential requirement for a direct recruitment.*—A candidate for appointment to any service or post must be:—

- (a) a citizen of India, or
- (b) a subject of Nepal, or
- (c) a subject of Bhutan, or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India.
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries or Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malwa, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

15. *Selection for appointment to post by direct recruitment.*—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of *viva-voce* test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc., of which, will be determined by the commission/other recruiting authority as the case may be.

16. *Reservation.*—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Backward Classes, other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. *Departmental examination.*—(1) Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Departmental Examination Rules, 1976 as amended from time to time, failing which he shall not be eligible to:—

- (i) Cross the efficiency bar next due;
- (ii) Confirmation in the service even after completion of probationary period; and
- (iii) promotion to the next higher post;

Provided that an officer who has qualified the Departmental Examination in whole or in part prescribed under any rules before the notification of these Rules shall not be required to qualify the whole or in part, of the examination as the case may be.

Provided further that an officer for whom no departmental examination was prescribed prior to the notification of these rules and who has attained the age of 45 years on the 1st March, 1976 shall not be required to qualify the departmental examination prescribed under these rules.

Provided further that an officer for whom no departmental examination was prescribed prior to the notification of these rules and who had not attained the age of 45 years on 1-3-1976 shall not be required to qualify the departmental examination prescribed under these rules after attaining the age of 50 years for the purpose of (i) Crossing of efficiency bar next due and (ii) confirmation in the service after completion of probationary period.

2. An Officer on promotion to higher post in his direct line or promotion shall not be required to pass the aforesaid examination if he has already passed the same in the lower gazetted post.

3. The Government may in consultation with the H.P. Public Service Commission, grant in exceptional circumstances and for reasons to be reduced to writing, exemption in accordance with the Departmental Examination Rules to any Class or category of persons from the Departmental Examination in whole or in part provided that such officer is not likely to be considered for any other higher promotion before the date of his superannuation.

18. *Power to relax.*—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P. Public Service Commissioner relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

By order,
O. P. YADAV,
Secretary.

TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 19th September, 1987

No. 2-28/83-STV (stipend).—In exercise of the powers vested in him, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to amend further, the Himachal Pradesh Technical Education Scholarship Rules, 1981, as amended from time to time retrospectively with effect from 1986-87.—

AMENDMENT

1. (i) These rules shall be called the Himachal Pradesh Technical Education Scholarships (Amendment) Rules, 1987.

(ii) These rules shall come into force at once.

Rule 12 of the aforesaid original rules shall be amended and substituted to read as under.—

“The Scholarships will be restricted to students who join courses in Himachal Pradesh or are nominated by the State Government or selected through the Regional Engineering College, Hamirpur for courses outside Himachal Pradesh. Students for other courses which are not available within Himachal Pradesh shall also be eligible, even if they are studying outside in Himachal Pradesh.”

ATTAR SINGH,
F.C.-cum-Secretary.

TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st July, 1987

No. TD (A) 4-7/82.—In exercise of the powers vested in him under Rule 9 of the Himachal Pradesh Tribes Advisory Council Rules, 1976, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to re-constitute the Himachal Pradesh Tribes Advisory Council for the Areas declared as Scheduled Areas in Himachal Pradesh *vide* para 2 of the Scheduled areas Himachal Pradesh order 1975, with immediate effect for two years as under.—

- | | |
|---|------------------|
| 1. Shri Virbhadra Singh, Chief Minister, Himachal Pradesh | <i>Chairman.</i> |
| 2. Shri Piru Ram, Minister of State for Welfare | <i>Member.</i> |
| 3. Shri Dev Raj Negi, Deputy Speaker, Himachal Pradesh Vidhan Sabha, Shimla-4 | <i>Member.</i> |

4.	Shri Devi Singh, M.L.A. Yates Cottage, Shimla-2	Member.
5.	Shri Thakur Singh, M.L.A., Metropole Hotel, Shimla-1	Member.
6.	Shri Subhash Negi, Village & P.O. Sangla, District Kinnaur, Himachal Pradesh	
7.	Kumari Rattan Manjari Devi, Village & P.O. Ribba, District Kinnaur, Himachal Pradesh	Member.
8.	Shri Jagat Singh Negi, Advocate, Village & P.O. Kalpa, District Kinnaur	Member.
9.	Shri Devinder Singh Negi, Village & P.O. Meeru, District Kinnaur, Himachal Pradesh	Member.
10.	Shri Chherring Bhag, Village & P.O. Pooh, District Kinnaur	Member.
11.	Shri Dharampal, Village Tholang, P.O. Tandi, District Lahaul & Spiti, Himachal Pradesh	Member.
12.	Shri Shushil Barongpa, Bandrole Orchard, P.O. Bandrol, Tehsil & District Kullu	Member.
13.	Shri Bir Singh, Village Chimret, P.O. Udaipur, District Lahaul & Spiti	Member.
14.	Shri Phunchog Rai, Village Lari, P.O. Tabo, District Lahaul-Spiti	Member.
15.	Shri Sonam Chhoprl, Village & P.O. Kaza, District Lahaul-Spiti, Himachal Pradesh	Member.
16.	Shri Ram Charan, Village Sali, P.O. Saach, Tehsil Pangi, District Chamba	Member.
17.	Shri Devi Singh, Village & P.O. Killar, Tehsil Pangi, District Chamba, Himachal Pradesh.	Member.
18.	Shri Kartar Singh, Village Chaled, P.O. Grima, Tehsil Bharmour, District Chamba	Member.
19.	Shri Zalam Ram, Village & P.O. Durgathi, Tehsil Bharmour, District Chamba	Member.

2. While the members at Sl. No.3 to 5 shall continue to hold office as members of this Council during the tenure of their membership of Himachal Pradesh Legislative Assembly, the members at Sl. No. 6 to 19 shall hold office for a period of two years from the date their nomination as provided under Rule 5 (2) and (3). But such nominated members (Sl. No. 6 to 19) can be removed before the expiry of his/her/their terms of two years at the pleasure of Governor.

3. The officials/non-official members of this Council will be entitled to draw travelling and daily allowance as under:—

- (i) The official members will be entitled to travelling allowance & daily allowance according to the rules governing them in their official capacity;
- (ii) The non-official members of this council will be entitled to draw T.A. and D.A. as per details given in the Annexure.

4. The Director (Welfare) Himachal Pradesh, Shimla will be the Controlling Officer for payment of T.A. to the Non-official Members.

ANNEXURE

T. A. AND D. A. TO NON-OFFICIAL MEMBERS OF THE COMMITTEE

A. Travelling Allowance :

(i) *Journey by Rail.*—They will, be treated at par with Government Servants of the first grade, and will be entitled to actual rail fare of the class of accommodation actually used but not exceeding the fare in which the Government servants of the First Grade are normally entitled, i.e. accommodation of the highest class by whatever name it may be called provided in the railway by which the journey is performed.

(ii) *Journey by Road.*—They will, be entitled to actual fare for travelling by taking single seat in a public bus, and if the journey is performed by motor cycle/scooter, mileage allowance at 60 paise per Km. for plain areas and 80 paise per Km. in the hilly areas, or if journey is performed by full taxi/own car, the member will be entitled to mileage allowance at Rs. 2.00 per Km**.

(iii) In addition to actual fare of mileage as per item (i) and (ii) above, a member shall draw daily allowance for the entire absence from his permanent place of residence beginning with departure from the place and ending with return to that place, at the same rate subject to the same terms and conditions as apply to Grade-I Officers of the State Government.

2. *Daily Allowance.*—(i) Non-official members will be entitled to draw daily allowance for each day of the meeting at the highest rates as admissible to a Government servant of the first grade for the respective locality.

(ii) In addition to daily allowance for the day (s) of the meeting, a member shall also be entitled to daily allowance for halt on tour and out-station in connection with the affairs of the Committee as under:—

(a) If the absence from headquarters does not exceed 6 hours	Nil.
(b) If the absence from headquarters exceed 6 hours but does not exceed 12 hours	70%.
(c) If the absence from Headquarters exceed 12 hours	Full.

** in respect of journeys in the plains and Rs. 2.50 per km. in the hills.

3. *Conveyance Allowance.*—A member, resident at a place where the meeting of the Committee is held will not be entitled to travelling and daily allowance on the scales indicated above, but will be allowed only the actual cost of conveyance hire, subject to a maximum of Rs. 10.00 per day. Before the claim is actually paid for, the Controlling Officer should verify the claims and satisfy himself after obtaining such details as may be considered necessary, that the actual expenditure was not less than the amount claimed.

If such a member uses his own car, he will be granted mileage allowance, at the rates admissible to officers of the first grade subject to a maximum of Rs. 10.00 per day.

4. The members will be eligible for travelling allowance for the journey actually performed in connection with the meetings of the Committee, from and to the places of their permanent residence to attend a meeting of the Committee or return to the place other than the place of his permanent residence after the termination of the meeting. Travelling allowance shall be worked out on the basis of the distance actually travelled or the distance between the place of permanent residence at the venue of the meeting whichever is less.

6. *Members of the Parliament.*—The members of the Parliament on the Advisory Committee in respect of journey performed by him by rail, road, air and steamer in connection with the work of Committee, shall be entitled to TA/DA on the same scale as is admissible to him under Salaries and Allowances of Members of Parliament as amended from time to time.

7. *Members of Vidhan Sabha.*—The non-official members who are members of the Vidhan Sabha shall be entitled to TA/DA in respect of Journeys performed in connection with the work of the Committee on the scale as is admissible to them under the Salaries and Allowances of Members of Legislative Assembly.

8. The members will not be entitled to daily allowance in connection with their assignment when the Vidhan Sabha or the Vidhan Sabha Committee on which the members are serving is in Session as they will be drawing their daily allowance under the Salaries and Allowances of Members of the Legislative Assembly Himachal Pradesh Act, 1971, from the Vidhan Sabha. However,

if they certify that they were prevented from attending the session of the House or the Vidhan Sabha Committee and did not draw any daily allowance from Vidhan Sabha they would be entitled to daily allowance at the rates as prescribed:

Provided that claims on account of travelling, halting and incidental allowances of members for attending the meetings of Committees appointed by the Government shall be paid after these have been countersigned by the Secretary Vidhan Sabha, for encashment.

9. The provision of rules 4.17 and 6.1 of the Himachal Pradesh Treasury Rules will apply *mutatis in the case of over payment made on account of Travelling Allowance to non-official members.*

10. The member will also not draw TA and DA including conveyance allowance which will disqualify them from the Vidhan Sabha.

OFFICIAL MEMBERS

11. The official Members shall be entitled to the travelling and daily allowance admissible to them according to the rules governing them.

By order,
A. N. VIDYARTHI,
Financial Commissioner-cum-Secretary.

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी मण्डल, मण्डी, हिमाचल प्रदेश

आदेश

मण्डी, 29 अगस्त, 1987

विषय.—हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के प्रधीन कारण बताओ नोटिस।

संबंधी पी0सी0 एन-मण्डी-ए (8) 16/83.—यह कि श्री कन्हैया लाल आदि, निवासी पंचायत क्षेत्र घिस्ती, तहसील चच्चोट, जिला मण्डी द्वारा श्री बृजलाल, प्रधान ग्राम पंचायत घिस्ती के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की प्रारम्भिक छान बीन पंचायत निरीक्षक गौहर से करवाई गई;

और यह कि जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ कि प्राथमिक पाठ्याला जैल के निर्माण हतु खण्ड विकास गौहर से मु0 50,160.00 रुपये अनुदान प्राप्त हुआ। उक्त स्कूल पर मु0 76,945.00 का व्यय होने का अनुमान था। मु0 26,785.00 लोगों द्वारा श्रमदान के रूप में योगदान करना था। परन्तु उक्त स्कूल भवन पर मु0 067,300.94 व्यय कर दिए। इस तरह सभा निधि से 17,140.94 रुपये व्यय किए। इस राशि में से केवल सभा निधि से व्यय करने हेतु प्रशासक पंचायत समिति गौहर से मु0 10,000.00 की स्वीकृति प्राप्त की है फिर भी मु0 7,140.94 पै0 0 अनाधिकृत व्यय किया गया है। इसके अतिरिक्त मु0 8,179.00 रुपये की राशि अभी तक श्रमिकों को देय है। उक्त स्कूल भवन का जो मूल्यांकन हुआ उसके अनुसार कुल व्यय मु0 69,118.83 बनता है। इससे स्पष्ट है कि उक्त श्री बृजलाल प्रधान ने नियमी को एक तरफ रख कर स्कूल भवन निर्माण पर मु0 75,479.94 व्यय कर दिए जब कि मूल्यांकन 69,118.83 होता है।

और यह कि प्रथम तो उक्त श्री बृज लाल, प्रधान ने अनुमान को ध्यान में न रख कर असीमित व्यय करके सभा निधि को मु0 7140.94 पै0 की हानि पहुंचाई है। इसरे मु0 8,179.00 श्रमिकों को उनकी मजदूरी न दे कर पंचायत की साथ को बिगड़ा है। जिस के आधार पर वह अनाचार तथा सभानिधि के दुरुपयोग को दोषी है।

अतः मैं, पी० सी० कपूर, अतिरिक्त उपायुक्त, मण्डी मण्डल, मण्डी, हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली 1971 के नियम 77 के प्रधीन शादेश देता हूँ कि वह कारण बताएँ कि क्यों न उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अधीन प्रधान पद से निलम्बित किया जाए। और क्यों न उन पर मु० 7,140.94 पै० जो सभानिधि से अनियमित व्यय करने तथा मु० 8,179.00 जो श्रमिकों को देय है का दायित्व निश्चित किया जाए। उन का उत्तर इस कारण बताओ नोटिस के जारी होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर-भीतर इस कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा आगामी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

हस्ताक्षरित/-
पी० सी० कपूर,
अतिरिक्त उपायुक्त,
मण्डी मण्डल; मण्डी।

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 21 सितम्बर, 1987

संख्या पी० सी० एच-एच० ए० (9)-44/76-3.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (1970 का 19) की धारा 163द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जनरल) फाइनैशियल, बजट, एकाउन्ट्स, आडिट, टैक्सेशन, सर्विस एण्ड एलाउन्सिस रूल्ज़, 1975 जिनका सरकार की अधिसूचना संख्या पी० सी० एच-एच० ए० (9) 44/76-2 तारीख 5 मार्च, 1987 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) तारीख 11-4-1987 में पूर्व प्रकाशन किया जा चुका है, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, प्रर्थतः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जनरल) फाइनैशियल, बजट, एकाउन्ट्स, आडिट, टैक्सेशन, सर्विस एण्ड एलाउन्सिस (संशोधन) रूल्ज़, 1987 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत होंगे।

AMENDMENT

The words and figures "Rs. 12 per day" and "Rs. 10 per day" appearing in category I and II in sub-rule (1) of rule 190 of Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Financial, Budget, Accounts, Audit, Taxation, Services & Allowances Rules, 1975, as amended *vide* this department notification of even number, dated the 28th August, 1981, shall be substituted by the words and figures "Rs. 25 per day" and "Rs. 20 per day" respectively and proviso to this sub-rule shall be deleted.

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित/-
अधर सचिव।

[Authoritative English text of Government notification No. PCH-HA(9)-44/76-3, dated 1st September, 1987 is hereby published in the Rajpatra, Himachal Pradesh as required under clause 3 of Article 348 of the constitution of India.]

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st September, 1987

No. PCH-HA (9)-44/76-3.—In exercise of the powers conferred by section 163 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1968 (Act No. 19 of 1970), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following amendment in the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Financial, Budget, Accounts, Audit, Taxation, Services and Allowances Rules, 1975, the same have been previously published in the Rajpatra (Extraordinary), Himachal Pradesh dated 11-4-1987 *vide* Government Notification No. PCH-HA. (9) 44/76-II, dated 5th March, 1987, namely.—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Financial, Budget, Accounts, Audit, Taxation, Services and Allowances (Amendment) Rules, 1987.

(2) These rules shall come into force at once.

2. *Amendment of rule 190.*—For the words and figures "Rs. 12/- per day" and "Rs. 10/- per day" of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (General) Financial, Budget, Accounts, Audit, Taxation, Services and Allowances Rules, 1975, the words and figures "Rs. 25/- per day" and "Rs. 20/- per day" shall be substituted respectively and the existing proviso to this sub-rule shall be deleted.

By order,
Sd/-
Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।